वाहवाही लूटना ही था नोटबंदी का मकसद

रणदीप सुर्जेवाला

लगा के आग शहर को, ये बादशाह ने कहा
उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत
झुकाके सर को सभी शाह-परस्त बोल उठे
हुजूर शौक सलामत रहे, शहर और बहुत !

इस लेख के ऊपरलिखित शीर्षक को पढ़कर घबराइए नहीं, क्योंकि यह एक व्यंग्य है, पर यही नोटबंदी की सच्चाई भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी सत्यपूर्ण जिम्मेदारी कभी नहीं ली, पर '' दिल को बहलाने को 'गालिब' ये ख्याल अच्छा है !'' नोटबंदी द्वारा मोदी जी ने जनता को जिस तरह से सताया है, उस महा-धोखे की भरपाई, इतिहास में शायद ही कोई कर सके। जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए जनता के हितों से खिलवाड़ करता था, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 125 करोड़ जनता को नोटबंदी के आनन-फानन भरे फैसले से सस्ती राजनीतिक वाहवाही बटोरने के लिए ठग लिया है। नोटबंदी के बाद तो अब सनकी मोहम्मद बिन तुगलक भी सोच रहा होगा कि उससे बड़ा सनकी अब भारत की धरती पर अवतरित हो गया है!

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि नोटबंदी के पश्चात भारतवासियों ने अपना सारा पैसा (99 प्रतिशत) नकदी व्यवस्था में वापस कर दिया है। नोटबंदी के कारण 15.45 लाख करोड़ का नकद अमान्य घोषित हुआ था, पर भारत के नागरिकों ने उसमें से 15.28 लाख करोड़ की राशि लौटा दी। यानी मात्र 16000 करोड़ ही आर्थिक तंत्र में वापस न आ सके। समझने वाली बात यह है कि इन 16000 करोड़ को खोजने के लिए भाजपा सरकार ने अपना पूरा सरकारी तंत्र झोंक दिया। कुल 25391 करोड़ तो सिर्फ संचालन और नए नोट छापने में ही लग गए। किसी भी पांचवीं कक्षा के बच्चे से भी अगर हम इस साधारण गणित का उत्तर पूछेंगे तो वह इसको नुकसान ही बताएगा। 8 नवंबर, 2016 की रात जब महान शक्तिशाली, राजनीतिक सूझ-बूझ से ओत-प्रोत, प्रशासकीय अनुभव से लैस मोदी जी ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब वह नोटबंदी का यह 'विशालकाय हवन' संपन्न करेंगे तो इसका परिणाम इतना उल्टा निकलेगा।

नोटबंदी का सबसे बड़ा झूठ तो प्रधानमंत्री जी ने लालकिले की प्राचीर से इस साल बोल दिया था। उन्होंने न पचने वाला एक ऐसा सफेद झूठ इतने बेबाक तरीके से बोला कि 'झूठ' पर अध्ययन करने वाले बड़े-बड़े मनोवैज्ञानिक और पेशेवर चिकित्सक भी शरमा जाएं। उन्होंने यह दावा किया कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था में लौट आए हैं। अब 16000 करोड़ के आधिकारिक खुलासे के बाद, मोदी जी अभी तक मौन हैं और उनके वित्तमंत्री जेटली जी फिर एक अच्छे विधिशास्त्र के विद्यार्थी की तरह कानूनी तर्क-वितर्क दिए जा रहे हैं।

नोटबंदी को लेकर सरकार के प्रवक्ता समय-समय पर, वस्तुस्थिति के मुताबिक, अपने लक्ष्य और उद्देश्य एक लटकन (पेंडुलम) के मुताबिक झुलाते रहे और देश की 125 करोड़ जनता इस तमाशे को झेलती रही। 8 नवंबर, 2016 को रात्रि के 8 बजकर 20 मिनट पर जब नोटबंदी का भूचाल हमारे ऊपर गिरा, तब इसका उद्देश्य कालेधन को खत्म करना व नकली नोटों से चल रहे आतंकवाद और नक्सलवाद के विनाशकारी धंधे की कब्र खोदना था। नोटबंदी से न कालाधन खत्म हुआ और न ही नकली नोट, न आतंकवाद का घिनौना

चेहरा और न ही नक्सलवाद की साजिशें ! गौर फरमाने वाली बात है कि नोटबंदी के बाद नवम्बर, 2016 के बाद हुए 36 बड़े आतंकवादी हमलों में, जम्मू-कश्मीर में अकेले, 46 लोगों की जान चली गई और 58 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस फैसले के बाद हुए 13 घातक नक्सली हमलों में 81 लोगों की जाने गईं व 69 जवान शहीद हो गए।

नोटबंदी की कथा का एक और अध्याय यह है कि उसके लागू होने के कुछ ही हफ्तों बाद भाजपा की गिरगिट-रूपी सरकार ने यह कहा कि यह 'महान कार्य' उसने देश को 'कैशलेस' बनाने के लिए किया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने डेबिट-क्रेडिट कार्ड और टेक्नोलॉजी के अन्य माध्यमों से भुगतान कर सकें। 'डिजिटल इंडिया' को प्रोत्साहन देना तो सिर्फ एक बहाना साबित हुआ है, असल में नोटबंदी की भीषण विफलता को जो बचाना था। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट ने इस दावे का भी पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 'डिजिटल ट्रांजैक्शन्स' दिसंबर 2016 के महीने पर तो बढ़ी पर मार्च 2017 के आते-आते वही पुराने स्तर पर आ गिरे। जाहिर है कि नोटबंदी के दौरान तो लोगों ने अपने कार्ड और मोबाइल भुगतान के माध्यमों का इस्तेमाल किया, क्योंकि नकद कम था पर इतने प्रचार भरे 'डीजीधन मेलों' और 'भीम ऐप' होने के बावजूद- खरे नकद पर से अपना नाता नहीं तोड़ा !

मोदी जी की महान सरकार ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का एक और लक्ष्य है- ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठित क्षेत्र की मुख्यधारा में लाकर टैक्स का फैलाव बढ़वाना। यह भी अच्छा मजाक है, सीएजी की रिपोर्ट ही इस दावे का भंडाफोड़ करती है। सरकार कह रही है कि इस साल अगस्त तक 2.82 करोड़ लोगों ने आयकर विभाग को अपना कर दाखिल किया पर हाल ही की सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल (2015-16) इससे अधिक 3.98 करोड़ लोगों ने आयकर विभाग को अपना कर दाखिल किया था।

नोटबंदी न सिर्फ एक आर्थिक त्रासदी है अपितु एक सामाजिक त्रासदी भी है। देश की अर्थव्यवस्था में 90 प्रतिशत योगदान देने वाला अनौपचारिक-असंगठित क्षेत्र नोटबंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। किसानों के पास नई फसल बोने के पैसे नहीं थे, ग्रामीण भारत में हाहाकार मचा हुआ था। गलियों में सामान बेचने वाले, फेरीवाले, रेहड़ी-पटरी वाले, खाने-पीने के खोमचे, बढ़ई, नाई, धोबी , कारीगर, बिजली कारीगर, रिपेयरमैन, प्लम्बर, पोटर एवं अन्य कारीगर, कपड़े के व्यापारी, किराना दुकान मालिक, बेकरी, सब्जी वाले और सब्जी के व्यापारी, अनाज के व्यापारी और विक्रेता, छोटे व्यापारी एवं दुकानदार आदि सभी इस फैसले से प्रभावित हुए थे। 100 से अधिक लोगों की लाइनों में लगकर जान चली गई थी। वह चाहे तनावग्रस्त अवस्था में दिल का दौरा पड़ने से हुई हो या अस्पतालों में भर्ती रोगियों को समय पर उपचार न मिलने की वजह से हुई हो ! इन सब परिवारों को भाजपा सरकार ने मुआवजा देना तो दूर संसद में शोक संवेदना तक भी नहीं प्रदान की।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था कि नोटबंदी 'संगठित लूट' और 'कानूनी डाका' है जिससे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को बड़ा धक्का लगेगा। आज डॉ. मनमोहन सिंह की वह बात सच हो गई, क्योंकि भारत की आर्थिक गति अब मंद पड़ गई है। इसका जिम्मेदार केवल एक व्यक्ति ही है, क्योंकि उसने अपने व्यक्तिगत विकास के लिए देश को आर्थिक बर्बादी की राह पर छोड़ दिया है।